

श्वेता विजन

“नजरिया साफ, ख़ख़रें निष्पक्ष”

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

माननीय ग्
अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश,
नामपल्ली,
हैदराबाद ने चैस
एक्ट के मामलों
में 5 साल की
सजा सुनाई

2

रविवार 27 सितम्बर 2026 हैदराबाद से प्रकाशित WEBSITE : Shwetha.co.in संपादक : रघुराम राजू कालीदिंडी पुष्ट - 1 | अंक - 12 | वर्ष - 8 | मूल्य - 3रु

कडप्पा कुश्ती..

कडप्पा ज्व में अंदरूनी मतभेद चेन्नमसेट्टी मुरली का डर। माधवी रेड्डी पर आरोप आरोप कि पुराने ज्व कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया जा रहा है आलोचना कि बाहर से आए नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है कॉर्पोरेशन चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने की चुनौती



कडप्पा एक ऐसा जिला है जो दशक, 1 से दूर परिवार के राजनीतिक प्रभाव का केंद्र रहा है। ऐसे में, कडप्पा में 2024 के विधानसभा चुनाव में ज्व की हार पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम बन गई है। ज्व उम्मीदवार रेड्डीपागरी माधवी रेड्डी ने कडप्पा विधानसभा सीट 90,988 वोटों से जीती थी। अब, जैसे-जैसे कडप्पा में स्थानीय निकाय चुनाव पास आ रहे हैं, ज्व के अंदर अंदरूनी मतभेदों का उभरना चर्चा का विषय बन गया है। ज्व नेता चेन्नमसेट्टी मुरली द्वारा जारी ऑडियो में, उन्होंने डर। माधवी रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए, आरोप लगाया कि वह पार्टी के लिए काम करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर दूसरी पार्टियों से आए लोगों को तरजीह दे रही हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेशन चुनाव में अपने उम्मीदवारों को अपनी ताकत से जिताने की चुनौती देने से कडप्पा ज्व की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि, मुरली के आरोपों पर डर। गुट का जवाब भी इस विवाद को समझने में अहम होगा यह विवाद अब क्यों सामने आया है? कडप्पा की राजनीति में यही मुख्य सवाल है। लोकल बॉडी चुनाव में टिकट बांटना सिर्फ उम्मीदवारों को चुनने के बारे में नहीं है। यह यह तय करने की भी एक प्रक्रिया है कि पार्टी के अंदर कोई कितना महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेशन में हर डिबिजन के लिए एक उम्मीदवार चुना जाना है। किसे टिकट दिया

जाना चाहिए? क्या किसी पुराने कार्यकर्ता को दिया जाना चाहिए? क्या चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए किसी नेता को दिया जाना चाहिए? क्या लोकल लेवल पर किसी मजबूत व्यक्ति पर विचार किया जाना चाहिए? क्या खिखरकार, ये लोकल चुनाव कडप्पा ज्व के लिए एक अहम ऑर्गेनाइजेशनल टेस्ट बन रहे हैं। 2024 में असेंबली सीट जीतना एक पॉलिटिकल माइलस्टोन है, लेकिन अब कॉर्पोरेशन लेवल पर पार्टी को एक साथ लीड करना एक और टेस्ट है। एक तरफ, सत्ता में पार्टी होने के नाते, हमें डेवलपमेंट और सरकार के परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ, हमें टिकट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स, पुराने कैंडिड और नए शामिल हुए नेताओं समेत सभी को

कोऑर्डिनेट करना है। अगर इसा समय अंदरूनी मतभेद पब्लिक हो जाते हैं, तो विपक्ष के पास पॉलिटिकल तौर पर बात करने के लिए कुछ होगा। इसीलिए कडप्पा में अब असली लड़ाई सिर्फ ज्व बनाम टैक्न नहीं है। एक और अहम सवाल यह है कि चुनाव के मैदान में उतरने से पहले ज्व अपने घर को किस हद तक टीक करेगी। पार्टी लीडरशिप चेन्नमसेट्टी मुरली की चुनौती का जवाब कैसे देगी? माधवी रेड्डी गुट इस नाराजगी से कैसे निपटेगा? क्या कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के दौरान ये मतभेद और साफ होंगे? या पार्टी चुनाव से पहले अंदरूनी तौर पर कोई हल निकालेगी? कडप्पा की पॉलिटिक्स में असली दिलचस्पी अब इन्हीं सवालों में है।

एसआईआर पर बवाल के बीच सरकार और भाजपा ने साफ किया कि चुनाव आयोग के काम में कोई दखल नहीं है। अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

नई दिल्ली: भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (म्ह) ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के आरोपों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, चुनाव आयोग पर बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप लगा रही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा इसकी नर्तना करती है। प्रसाद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को एफ की पूरी प्रक्रिया को उचित माना, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी की ओर से इस प्रक्रिया को अदालत में



चुनौती दी गई थी, सबको सुनने के बाद कोर्ट ने एफ को सही ठहराया, उन्होंने टीएमसी के संदर्भ में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारी तैनात किए गए थे और उस समय उन पर हमला हुआ था ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता

अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (म्ह) टीतजशनिवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्त मौजूद थे। चुनाव आयोग के एक प्रेस नोट में कहा गया है कि एफ से जुड़े जितने फैसले हुए, वे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों की सहमति से हुए देश के विभिन्न हिस्सों में एफ संकड़ी कदम को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है सरकार की लाइन भी इसी से जुड़ती है कृकिंसी भी संस्था में आंतरिक मतभेद सामान्य हैं, अंतिम फैसले सर्वसम्मति से होते हैं, एफ अवैध मतदाताओं की सफाई है, राजनीतिक हथियार नहीं, सरार

अनमैण्ड और नोटिस वाले वोटर्स के घर जाकर दस्तावेज इकट्ठा करेंगे ठरु, ECI का फैसला



नई दिल्ली: विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एफ) के बीच, भारत निर्वाचन आयोग (म्ह) ने शनिवार को फैसला किया कि अगर किसी व्यक्ति को इस प्रक्रिया के दौरान मैप नहीं होने और ताकिक विसंगतियों के लिए नोटिस जारी किया गया है, तो बूथ स्तरीय अधिकारी (तस्) दस्तावेजों के संग्रह के लिए ऐसे व्यक्तियों के घरों का दौरा करेंगे और उसके बाद उन्हें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (म्ह) के निर्णय के लिए मध्यम पर अपलोड करेंगे यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संघु वाली चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा नई दिल्ली में मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक था। म्ह की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, ऐसे लोगों को सुनवाई के लिए म्ह म्ह दफ्तर बुलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में, जैसा म्ह तय करेगा, बेहतर होगा कि सुनवाई ऑनलाइन हो, जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी भी बड़े सदस्य को वोटर अपनी तरफ से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत (नजीबतपेमक) कर सकते हैं, ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी तय किया कि म्ह (जिला निर्वाचन अधिकारी) जरूरत के हिसाब से नाइट शैल्टर में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीब लोगों, बेघर लोगों आदि के लिए पर्याप्त हेल्प डेस्क बनाएंगे या स्पेशल कैंप लगाएंगे, यह बताते हुए कि एफ के लिए फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, म्ह ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय लिया गया कि गैर-एसआईआर अवधि के लिए, नियमों के अनुसार निर्धारित फॉर्म (निर्वाचकों के पंजीकरण नियम 1960) का उपयोग किया जाएगा, यह देखते हुए कि फील्ड ऑफिसर्स के पास उनकी वैधानिक शक्तियों के अनुसार म्ह म्ह

प्रणाली तक भूमिका-आधारित पहुंच है, म्ह ने कहा कि सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिशनर (म्ह) की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें म्ह म्ह के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, म्ह म्ह की समीक्षा करेंगी, यह समिति यह दोबारा जांच करेगी कि क्या यह प्रणाली अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करती है और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (म्ह) से मिले सुझावों के आधार पर पोर्टल में पहले ही कई अपग्रेडेशन किए जा चुके हैं। अगर फील्ड ऑफिसर्स को आगे किसी भी तरह के लचीलेपन की जरूरत होगी, तो उसे लागू कर दिया जाएगा, अब से, आईटी मॉड्यूल और पोर्टलों से जुड़ी सभी नई पहलों पर आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले अधिकारियों की समिति (म्ह) में चर्चा की जाएगी, दिल्ली और महाराष्ट्र में समय-सीमा बढ़ीसीईओ दिल्ली से प्राप्त अनुरोध पर ध्यान देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा है कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि आयोग द्वारा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, नोटिस और दावों और आपत्तियों के निपटारन की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, बयान ने यह भी का गया कि सीईओ महाराष्ट्र से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, महाराष्ट्र में दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की अवधि आयोग द्वारा 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, महाराष्ट्र में नोटिस और दावों और आपत्तियों के निपटारन की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यह भी तय किया गया कि आयोग की सभी मीटिंग के लिए एजेंडा पहले से भेजा जाएगा और मिनट्स जारी किए जाएंगे और सभी अधिकारियों की चर्चा (एनुअल परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट) हर साल दिसंबर में तय समय में पूरी की जाएगी अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए आयोग की मंजूरी ली जाएगी और आयुक्तों द्वारा आयोग के अधिकारियों को दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा यह हवाला देते हुए कि

बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों में शासित प्रदेशों में एसआईआर पहले ही पूरा हो चुका है, आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम एसआईआर के दौरान या उसके बाद छूट गया हो और युवा या पहली बार मतदाता सहित कोई भी व्यक्ति, निरंतर अपडेट की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए संबंधित ईआरओ को आवेदन कर सकता है। बयान में कहा गया है कि म्ह को इस प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं, म्ह, म्ह, म्ह तुरंत इन मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेंगे, नभेद पर आयोग का बयान चुनाव आयोग के भीतर शीर्ष अधिकारियों के बीच मतभेदों पर हाल की न्यूज रिपोर्ट के संदर्भ में, म्ह चुनाव ने दोहराया कि कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र आयोग या आईटी प्रभाग के किसी भी नैतिगत मामले से संबंधित नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग में प्रतिनिधित्व पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था, आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किए गए कार्य पुनर्वितरण आदेशों (घुता तम-कपेजतपइनजपवद बतकमते) को वास्तव में दोनों आयुक्तों के आदेशों के बाद भी लागू नहीं किया गया था, और डीईसी द्वारा आईटी प्रभाग पर रखी जा रही निगरानी को वास्तव में कमी वापस नहीं लिया गया था, बयान में कहा गया है कि आयोग ने हाल के महीनों में, पूरे देश में एफ समेत कई फैसले लिए हैं, सभी राज्यों के लिए 24 जून 2025 को एफ का ऑर्डर जारी किया गया था, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसके बाद पश्चिम बंगाल और 30 अन्य राज्यों के लिए एकमत से एसआईआर की मंजूरी दी गई थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 मई 2026 के ऑर्डर में सही ठहराया है, चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं की अंतिम संख्या तीसरे चरण के शेष 12 राज्यों में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही साफ होगी, गोवा के म्ह ने संबंधित

‘इंडिया’ ब्लॉक की बैठक में चुनाव आयोग में सुधारों और मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरने की योजना बनाई जाएगी.

नई दिल्ली: चुनाव आयोग में विवाद को लेकर कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (म्ह) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपना लिया है। इस गंभीर मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस 30 सितंबर को ‘इंडिया’ (फ्छक) ब्लॉक की एक अहम बैठक बुलाकर उनका समर्थन जुटाने की तैयारी में है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार 30 सितंबर को होने वाली ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के लिए ताकतों को कैसे एकजुट किया जाए, इसके साथ



ही राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विरोध करने के तरीकों, चुनाव आयोग में सुधारों और मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरने की योजना बनाई जाएगी, फ्छक। तसवव चावजमेज हंपदेज म्ह ल्व(ड) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध

प्रदर्शन के दौरान पुतला जलाया, (ए।छे)कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, ‘इंडिया’ गठबंधन की यह बैठक 29 सितंबर को होने वाली ‘कांग्रेस कार्य समिति’ (म्ह) की बैठक के ठीक एक दिन बाद होगी, जिसमें देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा उस दिन, यह गठबंधन संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक नया महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी चर्चा कर सकता है, इससे पहले, इतिहास में पहली बार इस गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए 12 मार्च को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को महाभियोग प्रस्ताव

माननीय गृह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नामपल्ली, हैदराबाद ने चैम्स एक्ट के मामलों में 5 साल की सजा सुनाई,

अमीर हुसैन, क्राइम ब्यूरो चीफ

वी. मणिकांता (पिता: वी. श्याम, उम्र: 27 साल, पेशा: प्राइवेट कर्मचारी, निवासी: रामनगर, मुशीराबाद, हैदराबाद) को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के कंस नंबर 236/2023 में दोषी ठहराया गया है। यह मामला च्च की धाराओं 354, 354। 354ब, 509, 506 और च्च एक्ट की धारा 7 (धारा 8 के साथ) और धारा 11 (धारा 12 के साथ) के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में, आरोपी को 05 साल की साधारण कैद और 8,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।

04-06-2023 को सुबह लगभग 11:30 बजे, पीड़िता (उम्र 11 साल) की माँ ने शिकायत दर्ज कराई कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी (मणिकांता), जो उनका पड़ोसी है, पीड़िता के साथ गलत व्यवहार कर रहा था। वह उससे गलत तरीके से बात करता था, उसके बाल खींचता था, और उसके हाथ-पैर खींचकर उसे परेशान करता था। वह उसके करीब आता था और उसके कपड़ों के बारे में गलत बातें कहता था। वह पूछता था कि उसने शर्ट्स क्यों पहने हैं और कहता था कि उसे कपड़े उतारकर बिना कपड़ों के घूमना चाहिए। वह उसके गाल भी छूता था। इसलिए, मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई और बयान दर्ज करने के लिए मामले को 'भरोसा' (टीनवें) केंद्र भेजा गया। 'भरोसा' टीम ने पीड़िता और उसके परिवार की मदद के लिए कई तरह की काउंसलिंग तकनीकें अपनाईं। इसके अलावा, उन्होंने लगातार फॉलो-अप सेशन और वर्कशॉप में शामिल करके उन्हें नैतिक और भावनात्मक सहायता दिया। सजा की खबर सुनकर परिवार बहुत खुश हुआ। जांच अधिकारी श्री सीएच. प्रसाद रेड्डी और श्री... के ठोस प्रयासों से यह संभव हुआ। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन (हैदराबाद) के इंस्पेक्टर जी. राज



गोपाल रेड्डी स्पेशल एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पी. जे. रामकृष्ण पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ए. राम रेड्डी लीगल काउंसलर टी. कल्पना और ए.आर. हिमा मेननय भरोसा टीम के अन्य सदस्य कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर श्रीमती के. शिवा ज्योति (च 31046, मुशीराबाद) और श्री बी. सुदर्शन (च 9398, आर्बिडस चैय तथा समन ड्यूटी पर तैनात श्री जी. श्रीकांत (च 9937) ने इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान बहुत अहम योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराया गया।

भरोसा सेंटर के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के इन मिले-जुले प्रयासों की बारीकी से निगरानी श्रीमती डॉ. लावण्या (वक्, महिला सुरक्षा), श्रीमती प्रसन्ना लक्ष्मी (वक्, महिला सुरक्षा, हैदराबाद) और पी. पद्मा (इंस्पेक्टर, भरोसा) ने की हैदराबाद के च.बी.सी. सज्जनार (च) ने सभी संबंधित लोगों के प्रयासों और आपसी तालमेल की सराहना की। हस्ताक्षर-उप-पुलिस आयुक्त (क्ल. बउउपेपवदमत वी च्वसपबम) महिला सुरक्षा, हैदराबाद शहर।

मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रमाण पत्रों से दाखिले का नया मामला, अधिवक्ता समेत चार अरेस्ट



रुद्रपुर: देहरादून के बाद उधम सिंह नगर जिले में भी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए फर्जी पत्र और कूटचित दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है। मामला बाजपुर तहसील क्षेत्र का है। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में संबंधित अभ्यर्थियों के बताए पत्र पर निवास नहीं करने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए एक अधिवक्ता समेत चार लोगों के खिलाफ बाजपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों का भी दोबारा सत्यापन शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर 23 सितंबर 2026 को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से सत्यापन के लिए प्राप्त प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई। बाजपुर तहसील क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन के लिए उधम जिलाधिकारी ऋचा सिंह के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व टीम ने स्थलीय जांच की जांच में हुआ खुलासा प्रशासन के अनुसार स्थलीय सत्यापन के दौरान संबंधित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों में दर्ज पत्र पर निवासरत नहीं पाए गए। इसके बाद प्रमाण पत्रों के साथ लगाए गए दस्तावेजों की संबंधित विभागों से जांच कराई गई। जांच में कथित तौर पर यह सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों ने स्थानीय लोगों की सहायता से गलत पत्र और कूटचित सहायों के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाए थे। परिजनों से की गई पूछताछ: इन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए किए जाने की बात सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित अभ्यर्थियों के परिजनों को तहसील में बुलाकर पूछताछ की, अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, उधम जिलाधिकारी बाजपुर, तहसीलदार बाजपुर और राजस्व टीम की मौजूदगी में परिजनों व अन्य संबंधित लोगों के लिखित बयान भी दर्ज किए गए। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन ने फर्जी पाए गए प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया। प्रशासन की ओर से बाजपुर कोतवाली में श्याम बिहारी भोजवाल पुत्र गेवन लाल निवासी दौलतपुर रोड बरखेड़ा तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश शिवम गांधी पुत्र बालजीत निवासी तुला रोड रुरपुर इज्जतनगर जिला बरेली उत्तर प्रदेश अर्चना पत्नी आशीष भारद्वाज निवासी मुंडियाकला, बाजपुर, उधम सिंह नगर रोहित पुत्र राजेंद्र निवासी हरलालपुर बाजपुर बाजपुर के एक अज्ञात अधिवक्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुराने प्रमाण-पत्रों की भी होगी जांच: पुलिस

चसंपदमत: क्यों अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार को हराना चाहते हैं अनंत सिंह? 11 साल के अदावत की इनसाइड स्टोरी समझिए

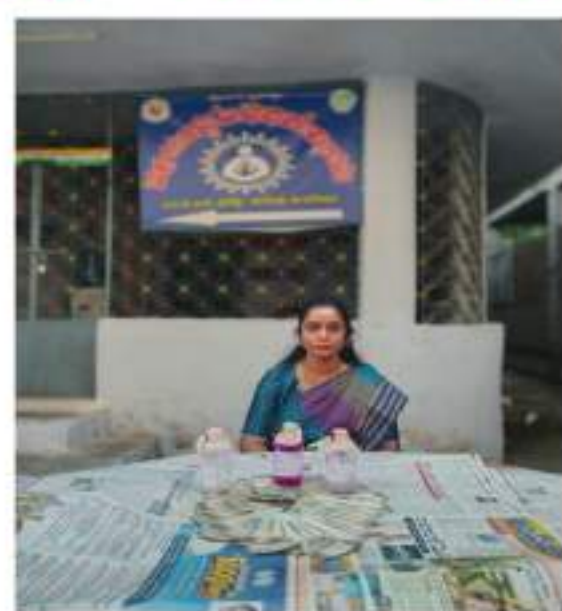


पटना : बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों पर चुनाव होना है। कई सीटों पर नुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। यहां जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के दो दिग्गज नेताओं के बयानों ने सियासी सरगमी बढ़ा दी है। पुराने साथियों में अदावत जदयू नेता नीरज कुमार चौथी बार पटना स्नातक क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ, मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने पार्टी में रहते हुए भी एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का खुलकर समर्थन कर दिया है। वे सार्वजनिक मंचों से नीरज कुमार को हराने का दावा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह अदावत कई वर्षों पुरानी है। अब चुनावी बहस में एके-47 से लेकर लालू प्रसाद तक का जिक्र होने लगा है। जे-47 का गंभीर आरोपविधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज कुमार की वजह से ही उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि उनके घर से जो एके-47 बरामद हुई थी, वह नीरज कुमार द्वारा ही प्लांट कराई गई थी। इसी साजिश के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि, नीरज कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट में सबूत पेश करने की चुनौती दी है। बदले की सियासी लड़ाई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में नीरज कुमार ने भी कई मौकों पर अनंत सिंह का कड़ा विरोध किया था। अब अनंत सिंह उसी का पुराना बदला ले रहे हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि वे अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ बहुत आगे तक नहीं जा सकेंगे। बहरहाल, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी जंग ने सूबे के राजनीतिक गलियारे में भारी हलचल पैदा कर दी है। वोटों का पुराना गणित दोनों नेताओं के बीच का यह विवाद करीब डेढ़ दशक पुराना है, जो साल 2015 के बाद से और ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले वर्ष 2005 और 2010 के चुनावों में नीरज कुमार ने अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था। लेकिन 2015 में सगीकरण बदले और अनंत सिंह वागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े। उस समय जेल में रहते हुए भी उन्होंने नीरज कुमार को 18,348 वोटों के अंतर से कराई शिकस्त दी थी। महावीर मंदिर में डिबेट का वीलेज अनंत सिंह का दावा है कि नीरज कुमार ने उन्हें हराने की चार बार कोशिश की, लेकिन जनता के समर्थन के कारण वे कभी सफल नहीं हो सके। उन्होंने नीरज कुमार पर पहली बार विधान परिषद का टिकट पाने के लिए पैर पगहावीर मंदिर में डिबेट का वीलेज अनंत सिंह का दावा है कि नीरज कुमार ने उन्हें हराने की चार बार कोशिश की, लेकिन जनता के समर्थन के कारण उन्हें हारने का भी आरोप लगाया, अनंत सिंह ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि नीरज कुमार पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में आकर उनके साथ सार्वजनिक डिबेट करें, ताकि सच सामने आ सके। 'मेरे घर में एके-47 नीरज ने ही प्लांट करवाया था' इसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा था। नीरज ने हमारा पैर पकड़ा, हमने नीतीश कुमार और ललन सिंह का पैर पकड़ा, तब नीरज को पहली बार विधान परिषद का टिकट मिला। महावीर मंदिर में डिबेट करें, हम बताएंगे कि नीरज ने मेरा कितना विरोध किया, कितनी गाली दी। नीरज ही बताएंगे

।ब्ल के जाल में फंसीं ब्वच्च (चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर), मेटपल्ली, जगित्याल जिला

अमीर हुसैन, क्राइम ब्यूरो चीफ

26.09.2026 को, मेटपल्ली, जगित्याल जिले की ब्वच्च श्रीमती दारोबु पद्मा (आरोपी अधिकाारी -) को ।ब्ल करीमनगर रूनिट ने रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने शिकायतकर्ता से 63,000 रुपये की रिश्वत मांगी और ली। यह रिश्वत मेटपल्ली अर्बन मंडल के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करने (यानी आधिकारिक पत्र लेने) के बदले मांगी गई थी। । ने 21 आंगनवाड़ी केंद्रों में से प्रत्येक से प्रति माह 1,000 रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी। इस प्रकार, तीन महीने की रिश्वत की कुल राशि 63,000 रुपये (21 केंद्र 3,000 रुपये) बनती थी। जाल बिछाने की कार्यवाई के दौरान, । ने अपने कार्यालय परिसर के बाहर शिकायतकर्ता से सीधे 63,000 रुपये की रिश्वत की राशि ली। रिश्वत की राशि । के पास से बरामद की गई। इस प्रकार, । ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अवैध



रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया। इसलिए, । को गिरफ्तार किया जा रहा है और न्यायिक रिमांड के लिए च और ।ब्ल मामलों के माननीय विशेष न्यायाधीश, करीमनगर के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले की जांच चल रही है। सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता का विवरण गुप्त रखा गया है। सेल फोन नंबर-1064 (टोल-फ्री नंबर): यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो जनता से अनुरोध है कि वे कानून के अनुसार कार्यवाई के लिए ।ब्ल के टोल-फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करें। ।ब्ल तेलंगाना से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप (9440446106), फेसबुक (जसवंतहंद ।ब्ल), और गूग्ल+ में ट्विटर (/जसवंतहंद ।ब्ल) के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। पीडित/शिकायतकर्ता का नाम और विवरण गुप्त रखा जाएगा। बील 26/9/2 पीआरओ/प्रवक्ता निरोधक ब्यूरो, टीजी, हैदराबाद।

कडप्पा कुश्ती..कडप्पा ज्वट में अंदरूनी मतभेद

चेन्नमसेट्टी मुरली का डर। माधवी रेड्डी पर आरोप आरोप कि पुराने ज्वट कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। आलोचना कि बाहर से आए नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कोर्पोरेशन चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने की चुनौती कडप्पा एक ऐसा जिला है जो दशकों से दै परिवार के राजनीतिक प्रभाव का केंद्र रहा है। ऐसे में, कडप्पा में 2024 के विधानसभा चुनाव में ज्वट की हार पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम बन गई है। ज्वट उम्मीदवार रेड्डीप्यगरी माधवी रेड्डी ने कडप्पा विधानसभा सीट 90,988 वोटों से जीती थी। अब, जैसे-जैसे कडप्पा में स्थानीय निकाय चुनाव

पास आ रहे हैं, ज्वट के अंदर अंदरूनी मतभेदों का उभरना चर्चा का विषय बन गया है। ज्वट नेता चेन्नमसेट्टी मुरली द्वारा जारी ऑडियो में, उन्होंने डर। माधवी रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए, आरोप लगाया कि वह पार्टी के लिए काम करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर दूसरी पार्टियों से आए लोगों को तरजीह दे रही हैं। इसके अलावा, कोर्पोरेशन चुनाव में अपने उम्मीदवारों को अपनी ताकत से जिताने की चुनौती देने से कडप्पा ज्वट की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि, मुरली के आरोपों पर डर। गुट का जवाब भी इस विवाद को समझने में अहम होगा।

यह विवाद अब क्यों सामने आया है? कडप्पा की राजनीति में यही मुख्य सवाल है। लोकल बॉडी चुनाव में टिकट बांटना सिर्फ उम्मीदवारों को चुनने के बारे में नहीं है। यह यह तय करने की भी एक प्रक्रिया है कि पार्टी के अंदर कोई कितना महत्वपूर्ण है। कोर्पोरेशन में हर डिवीजन के लिए एक उम्मीदवार चुना जाना है। किसे टिकट दिया जाना चाहिए? क्या किसी पुराने कार्यकर्ता को दिया जाना चाहिए? क्या चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए किसी नेता को दिया जाना चाहिए? क्या लोकल लेवल पर किसी मजबूत व्यक्ति पर विचार किया जाना चाहिए? व

बोराबंदा पुलिस ने अवैध 'बेल्ट शॉप' चलाने वाली श्रीमती वेमुला सरला के खिलाफ च्व एक्ट के तहत कार्रवाई की

अमीर हुसैन, क्राइम ब्यूरो चीफ

आज, यानी 26.09.2026 को, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्री वी.सी. सज्जनार (पै) के आदेशों के अनुसार, बोराबंदा पुलिस ने बोराबंदा की रहने वाली अवैध 'बेल्ट शॉप' (अवैध शराब बिक्री केंद्र) संचालिका श्रीमती वेमुला सरला के खिलाफ च्व एक्ट के तहत आदेश लागू किए।

26.09.2026 को, बोराबंदा पुलिस ने तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (च्व एक्ट) के प्रावधानों के तहत श्रीमती वेमुला सरला (पत्नी: पी. श्रीनिवासुलु, उम्र: लगभग 45 वर्ष, पेशा: गृहिणी, निवासी: बंजारा नगर, बोराबंदा, हैदराबाद) के खिलाफ च्व एक्ट के आदेश लागू किए। वेमुला सरला पिछले कुछ वर्षों से बोराबंदा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अवैध 'बेल्ट शॉप' चला रही थीं और शराब की अवैध बिक्री से जुड़े कई मामलों में शामिल थीं। ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों में उनकी लगातार संलिप्तता को देखते हुए ये आदेश लागू किए गए। अवैध बेल्ट शॉप चलाए जाने की अनधिकृत बिक्री के खिलाफ चेतावनी:

बोराबंदा पुलिस स्टेशन के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग बोराबंदा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में बिना पैप लाइसेंस के और आबकारी अधिनियम (न्यूपेन [न्यू] का उल्लंघन करते हुए अवैध 'बेल्ट शॉप' चला रहे हैं और शराब बेच रहे हैं। 'बेल्ट शॉप' चलाने वाले ऐसे सभी लोगों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे शराब की अवैध बिक्री तुरंत बंद करें। यदि कोई व्यक्ति 'बेल्ट शॉप' चलाते या अवैध रूप



से शराब बेचते हुए पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आदतन अपराधियों के खिलाफ च्व एक्ट लागू किया जाएगा। 'बेल्ट शॉप' के लिए जगह या आश्रय देने वाले

लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। आम जनता से अनुरोध है कि वे 'बेल्ट शॉप' चलाए जाने वाले की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखें। बोराबंदा पुलिस स्टेशन।

अब फूटक। गठबंधन मजबूत करने में जुटेंगी ममता! 30 सितंबर को ही सकती है बैठक, राहुल गांधी को भेजा संदेश

कोलकाता: विधानसभा चुनावों में हार पार्टी में फूट की घटनाओं से आहत ममता बनर्जी ने अब विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने का इरादा बना लिया है। चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और विपक्ष की रणनीति को तय करने के लिए इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होने की संभावना है। उन्होंने राहुल गांधी को इस संबंध में संदेश भेजा है कि 30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाए। मैंने राहुल को कहा कि हमें साथ बैठना चाहिए—ममता तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने हुगली जिले के श्रीरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संदेश भेजकर कहा है कि विपक्षी दलों को साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने यह बात मतदाता सूची के विरोध गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कही। ममता ने कहा, "मैंने राहुल गांधी को संदेश भेजकर कहा है कि हमें साथ बैठना चाहिए। 'इंडिया' गठबंधन की बैठक 30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने की संभावना है।" प्रस्तावित बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्षी दल निर्वाचन आयोग के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया को लेकर आपसी समन्वय की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ममता ने राहुल गांधी से फोन पर भी बात की और उनसे जल्द से जल्द 'इंडिया' गठबंधन की बैठक बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने माकपा महासचिव एमए बेबी से भी



बातचीत की। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़ी मुश्किलें दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद से ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्य से सत्ता जाने के बाद पार्टी भी उनके कंट्रोल में नहीं रही। सांसदों और विधायकों ने साथ छोड़ दिया। पहली फूट विधानसभा में हुई और बड़ी संख्या में विधायक टीएमसी से अलग हो गए। ममता बनर्जी अभी इस सदन से उबर भी नहीं पाई थीं कि उनके सांसद भी अलग होने लगे। अब तो पार्टी का चुनाव चिह्न भी आयोग ने बदल दिया है। एसआईआर के जरिये वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए—ममता वहीं ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिये वैध मतदाताओं

के नाम हटाकर राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में मदद की। हुगली जिले के श्रीरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने हाल ही में आई एक खबर का स्पष्ट संदर्भ देते हुए यह भी कहा, "भाजपा ने चुनाव आयोग का किस तरह इस्तेमाल किया, इसका सच अब सामने आ चुका है।" उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा देने तक देशभर में विरोध-प्रदर्शन जारी रहेंगे। मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से उनके मतदाता पहचान पत्र छीन रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का फैसला कर सबको चौंका दिया था। उस वक्त ममता खेमे की उम्मीदवार संयिता प्रधान ने मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी से मुलाकात के बाद चुनाव से नाम वापस ले लिया। इसके बाद ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया और इसे विपक्षी गठबंधन फूटक को मजबूत करने से जोड़ा था।

दिल्ली और महाराष्ट्र के 'फ' में आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिविजन (ए) के दौरान दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने शनिवार को रिविजन से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी दी। आयोग के अनुसार, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली में 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर तक आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख जानकारी के अनुसार, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 की गई। दिल्ली में नोटिस और दावे-आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 30



नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई। वहीं, महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 बढ़ा दी गई है। अब महाराष्ट्र में नोटिस और दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 की गई है। चुनाव आयोग की मीटिंग में लिए कई फैसले बता दें कि शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग के तीनों आयुक्तों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस

रिलीज जारी कर कहा, "अगर किसी ऐसे व्यक्ति को चल रही 'फ' के दौरान अनमिष्ट होने और लौजिकल गड़बड़ियों के लिए नोटिस जारी किया गया है, तो उस व्यक्ति को घबराहट से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हो, तो वोटर परिवार के किसी भी बड़े सदस्य को उनकी तरफ से सुनवाई में शामिल होने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। आयोग ने कहा कि 'फ' के लिए फॉर्म 6 के साथ अटैच की गई घोषणा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। नॉन-ए पीरियड के लिए नियमों (इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन

पीएम मोदी की अनकही कहानियों का यूपी में होगा नाट्यमंचन, रंगमंच पर दिखेगी 25 साल की सेवा यात्रा



पूर्व अध्यक्ष और जेएनयू के पूर्व वीसी एम. जगदेश कुमार, पूर्व रक्षा सचिव गिरीधर अरमाने, पूर्व पर्यावरण सचिव लीना नंदन और सीआईएसएफ की पूर्व महानिदेशक नौना सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर का नाम भी दस्तावेजों के मिलान न होने के कारण चर्चा में है। निर्वाचन आयोग की स्पष्ट सफाई, घबराने की जरूरत नहीं। देशभर में इस हाई-प्रोफाइल सूची के सामने आने के बाद और उठ रहे सवाल के बीच निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग का कहना है कि नोटिस मिलने मात्र से किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं माना जाएगा। यह केवल लॉजिकल डिस्क्रीमिनेशन या पिछले 'फ' डेटा से सीधे निकल न हो पाने के कारण एक सत्यापन प्रक्रिया है। आयोग के नियमों के मुताबिक, जिन भी मतदाताओं या अधिकारियों को नोटिस मिले है, वे संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (मन्त्र) के समक्ष अपने जरूरी दस्तावेज और सही विवरण प्रस्तुत कर प्रविष्टियों का सत्यापन करा सकते हैं। दिल्ली में चल रहे इस व्यापक अभियान के तहत 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 29 अक्टूबर तक सभी आपत्तियों और नोटिसों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले— भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जासूसी कर रहे

बहराइच : जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रविवार को बहराइच



दौर पर थे। उन्होंने राहुल गांधी व पूर्व उप राष्ट्रपति हमिद अंसारी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एनएसए चीफ अजीत डोभाल की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी द्वारा अजीत डोभाल पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है अपने अजीत डोभाल पर। राहुल गांधी ने जासूसी की है देश के खिलाफ और दूसरे देशों के पक्ष में। उन्होंने कहा, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई जासूसी कर रहा है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। देश के लिए जिसने जासूसी की है उसका नाम है अजीत डोभाल। दोनों की तुलना निरन्तर एक सुरज और एक बया कहें, कुछ कह नहीं सकता हूँ इस स्तर की तुलना है। अजीत डोभाल भारत के लिए पाकिस्तान में नाई बन के रहे। चर्चा सुनते हैं कि कहीं दाढ़ी बना रहे थे, तो कहीं होटल में काम कर रहे थे। भारत के लिए किस-किस रूप में किया। दिनेश प्रताप सिंह का राहुल गांधी पर तंज, (टपकमव बतमकवजय छप)

प्राणों की बाजी लगा करके जो व्यक्ति भारत के लिए जासूसी करता हो, ऐसे जासूस पर मुझे गर्व है, हर भारतवासी को गर्व होगा। राहुल गांधी को सवाल उठाने के लिए भारत के संविधान ने और भारत की जनता ने अधिकृत किया है, तो लोकसभा में क्यों सवाल नहीं उठाते? जब लोकसभा में सवाल उठाने के लिए समय आता है, तो कंबोडिया में होते हैं, कहीं दूसरे देश में होते हैं, मौज-मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। भारत की जनता की सेवा के लिए और नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राहुल गांधी के पास समय नहीं है, केवल यह आरोप मिथ्या लगाते हैं कि किसी की बात सुनी नहीं जाती। हमारे यहां 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। सबको अवसर है, चाहे जो बात कहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी के दक्षिणपंथी हिन्दू सांप्रदायिकता को कम्युनलिज्म से ज्यादा खतरनाक बताने पर उन्होंने कहा कि जिस भारत ने उनको उपराष्ट्रपति के रूप में सम्मान दिया, जिस भारत की रोटी और नमक खा करके वो भारत के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इतनी ऊँचाइयों पर अगर भारत न होता, तो किसी दूसरे राष्ट्र में उपराष्ट्रपति जैसे पद पर सम्मान पाने का हक शायद हमिद को कभी न मिलता। प्राणों की बाजी लगा करके जो व्यक्ति भारत के लिए जासूसी करता हो, ऐसे जासूस पर मुझे गर्व है, हर भारतवासी को गर्व होगा। राहुल गांधी को सवाल उठाने के लिए भारत के संविधान ने और भारत की जनता ने अधिकृत किया है, तो लोकसभा में क्यों सवाल नहीं उठाते? जब लोकसभा में सवाल उठाने के लिए समय आता है, तो कंबोडिया में होते हैं, कहीं दूसरे देश में होते हैं, मौज-मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। भारत की जनता की सेवा के लिए और नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राहुल गांधी के पास समय नहीं है, केवल यह आरोप मिथ्या लगाते हैं कि किसी की बात सुनी नहीं जाती। हमारे यहां 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। सबको अवसर है, चाहे जो बात कहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी के दक्षिणपंथी हिन्दू सांप्रदायिकता को कम्युनलिज्म से ज्यादा खतरनाक बताने पर उन्होंने कहा कि जिस भारत ने उनको उपराष्ट्रपति के रूप में सम्मान दिया, जिस भारत की रोटी और नमक खा करके वो भारत के ऊपर इस

स्टाफ क्वार्टर निर्माण मामले में गरमाई
सियासत: छात्रों की गोपनीय बातें सार्वजनिक होने
पर अध्यक्ष अजय महावर ने जताई कड़ी आपत्ति



नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (एलए) के अध्यक्ष और विधायक अजय महावर ने समिति की कार्यवाही को सार्वजनिक करने और इसे राजनीतिक रंग देने के प्रयासों पर गंभीर आपत्ति जताई है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोक लेखा समिति पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से नियमों के दायरे में रहकर काम कर रही है और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी, इस पूरे मामले को विशेषाधिकार हनन के दृष्टिकोण से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। सोमवार को छात्र अध्यक्ष अजय महावर ने बताया कि लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्टाफ क्वार्टर के निर्माण से जुड़ा मामला समिति के पास जांच के लिए आया है, यह जांच पूरी तरह से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAI) की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों और पैराग्राफ 2.5 के दायरे में की जा रही है, समिति मुख्य रूप से इस बात की तथ्यात्मक जांच कर रही है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दरों के निर्धारण के लिए पुरानी दर प्रणाली का उपयोग क्यों किया गया और लागत अनुमान का आधार क्या था, इसके अलावा, निर्माण क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी और उससे जुड़े वित्तीय प्रभावों की भी बारीकी से समीक्षा की जा रही है निर्माण क्षेत्र और लागत में भारी वृद्धि पर सवाल दाल रिपोर्ट के अनुसार, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण क्षेत्र लगभग 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर करीब 1,905 वर्ग मीटर कर दिया गया था, इससे लगभग 18.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ा है स्टाफ ब्लॉक के निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, दाल के मुताबिक, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकृत धन का एक हिस्सा दूसरे मद में डायवर्ट किया गया, समिति यह जांच कर रही है कि यदि मूल योजना के अनुसार स्टाफ ब्लॉक नहीं बनाया गया, तो फंड के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी, इसके लिए सक्षम प्राधिकारी कौन था और संबंधित भुगतान किस आधार पर किए गए, पुराने क्वार्टरों को गिराने, नए निर्माण, ठेकेदारों की पात्रता और भुगतानों से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है,

अजय महावर ने कहा कि लोक लेखा समिति की कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय होती है और अंतिम रिपोर्ट आने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, हाल ही में जब स्टाफ क्वार्टर के मामले में दस्तावेजों की छानबीन चल रही थी, तब कुछ गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक दल आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन छात्र जैसी गरिमामयी संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है, समिति की गोपनीय सामग्री को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने और राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने के मामले को विशेषाधिकार के तहत विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाया जाएगा, प्रस्तावित साइट डिजिट स्थगित, जल्द होगी अगली कार्यवाही मामले को राजनीतिक रंग दिए जाने और स्वतंत्र जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों के चलते सोमवार को प्रस्तावित साइट निरीक्षण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि समिति पर दबाव बनाने के हर प्रयास को विफल किया जाएगा, विधानसभा के नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए, सभी आवश्यक परामर्श के साथ बहुत जल्द अगला साइट निरीक्षण किया जाएगा, उन्होंने दोहराया कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता लाना और दाल रिपोर्ट के सवालों के तथ्यात्मक उत्तर खोजना ही छात्र का मुख्य कार्य है,

5 रुपये से 40 रुपये तक पहुंचा कैं
शुल्क, छात्र संघ के 79 साल के सफर
में कई बार बदली व्यवस्था

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (कैं) का नाम आते ही छात्र राजनीति, चुनाव और चार प्रमुख पदों की तस्वीर सामने आती है, इसू के इतिहास का एक पहलू उसका शुल्क भी है, कैं के करीब 79 साल के सफर में सिर्फ चुनावी व्यवस्था ही नहीं बदली, बल्कि छात्रसंघ से जुड़ा शुल्क भी कई गुना बढ़ा है, विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक, 2012-13 तक छात्रों से कैं के लिए महज 5 रुपये शुल्क लिया जाता था, विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक, इसू शुल्क में सबसे पहले बड़ा बदलाव वर्ष 2013-14 में हुआ, जब इसे 5 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये किया गया, 6 अगस्त 1947 को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में छात्रों के प्रतिनिधि संगठन की स्थापना का प्रस्ताव सामने आया था, विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन कुल, पति ने परिषद को बताया था कि छात्रों का एक प्रतिनिधि समूह विश्वविद्यालय में छात्रों का संघ बनाना चाहता है, इसके लिए एक समिति गठित कर संविधान और कामकाज की प्रक्रिया तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया था, शुरुआती खर्च के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 150 रुपये की सहायता देने की उम्मीद भी जताई गई थी, यही प्रस्ताव आगे चलकर इसू के संस्थागत सफर की शुरुआती कड़ी बनाई दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी, लेकिन छात्रों के लिए अलग प्रतिनिधि संस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, इसी उद्देश्य से 9 अप्रैल 1949 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (कैं) की स्थापना की गई, इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उस समय छात्रसंघ का मुख्य उद्देश्य छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करना, छात्रों की समस्याओं को उठाना और विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण को मजबूत करना था, शुरुआती वर्षों में छात्रसंघ का गठन प्रत्यक्ष चुनावों से नहीं होता था, प्रतिनिधियों के माध्यम से छात्र नेतृत्व का चयन किया जाता था, छात्रसंघ बनने के बाद उसके सामने आर्थिक आत्मनिर्भरता की समस्या खड़ी हो गई, 27 मार्च 1953 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति के सामने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से आर्थिक सहायता की मांग रखी गई, उस समय विश्वविद्यालय ने कहा था कि छात्र संघ को खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करने चाहिए, रिकॉर्ड के मुताबिक, उस वर्ष संघ को पहले ही 500 रुपये की सहायता दी जा चुकी थी, इसके एक



‘पद्म भूषण बहुत छोटी चीज, पीएम बना दीजिए’,
ज्ञानेश कुमार पर पवन खेड़ा का तंज

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (बम्) ज्ञानेश कुमार पर उनके खिलाफ एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि सीईसी को इस्तीफा दे देना चाहिए और आरोप लगाया कि “चुनाव आयोग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं,” मीडिया से बातचीत के दौरान खेड़ा ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयान पर तंज कसा है, बता दें कि भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें कम से कम पद्म भूषण मिलना चाहिए, इसके जवाब में खेड़ा ने कहा कि पद्म भूषण तो बहुत छोटी चीज है, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए एसआईटीआर विवाद के बीच सीईसी के खिलाफ कार्यवाही की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनके अपने हित में होगा, उन्होंने कहा, “उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी सुरक्षा, उनके हित, उनके भविष्य की सुरक्षा इसी में है, जब मैं सुरक्षा कहता हूँ, तो मेरा मतलब उनके भविष्य की सुरक्षा से है, क्योंकि अगर वह सरकारी गवाह बन जाते हैं तो वह सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो, उनका आने वाला समय जेल में बीतेगा,” खेड़ा ने कहा कि एक अंग्रेजी अखबार की चौकाने वाली जांच से पता चला है कि मतदाता के चल रहे स्पेशल इंटेसिव रिविजन (पी) के बीच, चुनाव आयोग ने बीएलओ ऐप में एक खास ‘मार्क वीआईपी’ फीचर शुरू किया, उन्होंने कहा कि ये फीचर बूथ लेवल अधिकारियों को कुछ भारतीय मतदाताओं की पहचान करने और उन्हें वीआईपी के तौर पर मार्क करने की सुविधा देता है, कांग्रेस नेता ने कहा, “एपल ऐप स्टोर इस बदलाव को ‘मार्क वीआईपी वोटर से जुड़े बदलाव’ के तौर पर रिकॉर्ड करता है, ये किस तरह का वीआईपी कल्चर है? पीएम मोदी ने बार-बार खुद को ‘प्रधान सेवक’ बताया और दावा किया कि उनकी सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है, तो फिर



किसके कहने पर चुनाव आयोग ऐसा सिस्टम चला रहा है, जो वीआईपी वोटर्स और आम वोटर्स के बीच फर्क करता है?” उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग भारतीय वोटर्स को अलग-अलग क्यों कर रहा है और किस आधार पर ऐसा कर रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए खेड़ा ने दावा किया कि चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे मंत्रियों और उनके परिवारों, जजों, वकीलों, मशहूर हस्तियों, आईएस और आईपीएस अफसरों के अलावा नौकरशाहों, मीडियाकर्मीयों, समाज सेवकों और अन्य लोगों की पहचान वीआईपी के तौर पर करें, वहीं केंद्रीय मंत्री विराग

पासवान की इस टिप्पणी पर कि चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, खेड़ा ने कहा कि सिस्टम के अंदर से चिंताएं सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग के अंदर से आवाजें आ रही हैं, सरकार के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, अगर मोदी जी और शाह अभी नहीं सुन पा रहे हैं, तो यह हमारी गलती नहीं है, उन्हें अपने कान चेक करवाने चाहिए,” उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में कुछ पार्टियों के यह कहने पर कि भाजपा को जवाब देना चाहिए, खेड़ा ने कहा, “अभी बहुत लोग मोलेंगे, भाजपा के अंदर से भी आवाजें उठेंगी, इंतजार करो,

विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा के नेतृत्व में डेलीगेशन
ने माल्टा के सैन्य कब्रिस्तान में मेघालय के चार गारो
पुरुषों को श्रद्धांजलि दी.

शिलांग: मेघालय के एक डेलीगेशन ने भूमध्य सागर के द्वीप देश माल्टा के पीटा मिलिट्री कब्रिस्तान में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान की है, जो प्रथम विश्व युद्ध (१) के दौरान ब्रिटिश 69वीं गारो लेबर कंपनी का हिस्सा थे, अब तक, 15 जून 1918 को मरे खेप मारक की कब्र को ही कब्रिस्तान में 69वीं गारो लेबर कंपनी के गारो सदस्य की एकमात्र ज्ञात कब्र माना जाता था, अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मेघालय के चार गारो पुरुषों को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें राष्ट्रमंडल द्वारा संचालित सैन्य कब्रिस्तान में दफनाया गया है, संगमा ने मीडिया को बताया, “हमने माल्टा में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान कर ली है, हमें बताया गया कि वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों (एसएसएमक वित्तबे) की मदद करने आए थे,” इस दौरे के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने एडिंग मारक (कपदह डंतो) और जॉइन सामने लाया, जिनके योगदान और बलिदान काफी हद तक अज्ञात थे, इस प्रतिनिधिमंडल में डिप्टी स्पीकर लिमिटसन डी. संगमा, डिप्टी चीफ व्हिप रॉनी वी. लिंगदोह और मेघालय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष मार्थन जे. संगमा शामिल थे, मेघालय विधानसभा के सचिव माल्थस एस. संगमा और उपसचिव राजा खर्पुरी भी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ थे, थॉमस के अनुसार, माल्टा की यह यात्रा प्रतिनिधिमंडल के उस अध्ययन दौरे का हिस्सा थी, जो दक्षिण अफ्रीका के मारक (श्रवपद डंतो) की कब्रों की पहचान की, जिनकी मौत 10 जून, 1918 को हुई थी, और संगमिम संगमा (दहरपउ दहरउ) की कब्रों की भी



पहचान की, जिनकी मौत 19 जून, 1918 को हुई थी, गारो लेबर कंपनी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र से भर्ती की गई लेबर यूनिट्स में से एक थी, जिसके सदस्य सड़क निर्माण, रखरखाव और आपूर्ति के परिवहन जैसे काम करते थे, इस खोज ने मेघालय के इतिहास और विश्व युद्धों के दौरान मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में भारत के व्यापक योगदान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी को सामने लाया है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, संगमा ने कहा कि यह यात्रा मेघालय के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने गारो समुदाय के उन पुरुषों के अंतिम विश्राम स्थलों को सामने लाया,

जिनके योगदान और बलिदान काफी हद तक अज्ञात थे, इस प्रतिनिधिमंडल में डिप्टी स्पीकर लिमिटसन डी. संगमा, डिप्टी चीफ व्हिप रॉनी वी. लिंगदोह और मेघालय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष मार्थन जे. संगमा शामिल थे, मेघालय विधानसभा के सचिव माल्थस एस. संगमा और उपसचिव राजा खर्पुरी भी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ थे, थॉमस के अनुसार, माल्टा की यह यात्रा प्रतिनिधिमंडल के उस अध्ययन दौरे का हिस्सा थी, जो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (नवउवदूमसजी स्तसपउमदजंतल ववपजपवद) सम्मेलन में भाग लेने के बाद शुरू हुआ था,

हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के बाद यूपी के पशुपालकों की
उड़ी नींद, जानें कैसे करें लंपी वायरस से बचाव

मेरठ : हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सहित यूपी में भी लम्पी वायरस (संवर्चल पद कपेमम) पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे पशुपालक और विशेष रूप से गो पालकों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, ऐसे में मेरठ में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे पशुपालक परेशान हैं, आज हम आपको इस खबर में बताएंगे आखिर कैसे अपने पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं और अगर कोई गोवंश किसी तरह से लंपी वायरस की चपेट में भी अगर आ जाता है, तो भी कैसे उसे बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किये जा सकते हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के बाद यूपी के पशुपालकों की उड़ी नींद, (ईटीवी भारत) देश के कई राज्यों में पशुओं में लम्पी रिकन डिजीज का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे

में पशुपालक परेशान हैं, देश के कई राज्यों में लम्पी वायरस फैला हुआ है, लंपी वायरस से पशुपालकों की उड़ी नींद, (ईटीवी भारत) ऐसे में पशुपालन विभाग भी लगातार इस बीमारी की जाद में आने वाले पशुओं को बचाने के लिए भाग दौड़ करने की बात करता है, हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से वैक्सीन का भी प्रबंध किया जाता है, लेकिन आमतौर पर गोवंश में इस बीमारी के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं, लंपी बीमारी की वजह से पशु के अंदर खून की कमी हो जाती है और वह तड़प-तड़प कर मर जाता है, जिसके बाद ऐसे किसान पशुपालक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि बढ़ाते महंगाई के इस दौर में किसी के लिए भी पशु खरीदना अब आसान नहीं है, गाय-भैसों की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में

किसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है, जब उसका पशु बीमार हो जाए, और उसे बचाए ना जा सके, मेरठ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्रजीत सिंह से ईटीवी भा हरियाणा से फेली ये बीमारी, उत्तराखंड के रास्ते यूपी आई मेरठ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्र जीत सिंह ने बताया कि यह वायरस से फेलने वाली बीमारी है और पहले यह हरियाणा में आई थी और उसके बाद उत्तराखंड में आई और सहारनपुर से होते हुए अब इसका असर मेरठ में भी है, वह बताते हैं कि मेरठ को फायदा यह हुआ कि जैसे ही इसका प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ था, तभी मेरठ में इसकी वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू हो गई थी और शासन की तरफ से समय से वैक्सीन लेकर वैक्सीन भी लगाई जा रही है,

खराब फिटनेस बनाम फेफड़ों की समस्या: दोनों के बीच के अंतर को कैसे पहचानें?

बहुत से लोगों को रोजाना के काम करते समय सांस लेने में तकलीफ होती है, वे अक्सर सोचते हैं कि क्या यह सिर्फ मोटापे या फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से है, या यह फेफड़ों की किसी अंदरूनी समस्या की वजह से है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और चैर फिजिशियन डॉ. महावीर मोदी कहते हैं कि ऐसे कई मरीज उनके पास अक्सर यह सवाल लेकर आते हैं, वह मानते हैं कि यह एक सही चिंता है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ के कई कारण हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की कमी या खराब फिजिकल फिटनेस निश्चित रूप से रोजाना के कामों को और मुश्किल बना सकती है, हालांकि, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), ब्रोंकाइटिस और सांस की दूसरी बीमारियाँ जैसी बीमारियाँ से भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सबसे जरूरी बात यह है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सांस फूलने की समस्या कैसे होती है, यह कितनी देर तक रहती है और क्या इसके साथ कोई और लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि...

फिजिकल एक्टिविटी बंद करने के बाद कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं? सबसे आसान संकेतों में से एक यह है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बंद करने के बाद कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, अगर सांस लेने में तकलीफ मुख्य रूप से खराब फिटनेस की वजह से है, तो आमतौर पर आराम करने के कुछ मिनट बाद आपकी सांस नॉर्मल हो जाती है, हालांकि, अगर आराम करने के बाद भी सांस फूलना 10-15 मिनट या उससे ज्यादा समय तक रहता है, खासकर अगर ऐसा बार-बार होता है, तो यह किसी अंदरूनी मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है जिसके लिए



जांच की जरूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज पर शरीर का रीस्पॉन्स डॉ. महावीर मोदी के मुताबिक, एक और जरूरी बात यह है कि आपका शरीर रेगुलर एक्सरसाइज पर कैसा रीस्पॉन्स देता है, अगर आप बस अनफिट हैं, तो धीरे-धीरे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से समय के साथ आपका स्टैमिना बेहतर होगा, कुछ हफ्तों तक लगातार चलने या दूसरी सही एक्सरसाइज करने के बाद, आप देखेंगे कि वही एक्टिविटीज सांस लेने में कम दिक्कत पैदा करती हैं, इसके उलट, अगर फेफड़ों में कोई अंदरूनी दिक्कत है, तो फिजिकल एक्सरसाइज से खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो सकते हैं, सांस से जुड़े अन्य लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने या दौड़ने जैसी शारीरिक मेहनत करने पर सांस फूल सकती है और मांसपेशियों में थकान हो सकती है, हालांकि, आराम करने पर यह आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाता है, अगर सांस फूलने के साथ-साथ लगातार खांसी, सांस लेते समय घरघराहट या बहुत ज्यादा बलगम बनने जैसी समस्या हो, तो यह अस्थमा, COPD या सांस के किसी अन्य संक्रमण का संकेत हो सकता है,

ध्यान दें कि सांस फूलने की समस्या कब होती है डॉ. महावीर मोदी का कहना है कि यह ध्यान देना भी जरूरी है कि सांस फूलने की समस्या कब होती है, डॉकडीशनिंग की वजह से आमतौर पर ज्यादा मेहनत वाले कामों, जैसे कई मजिल सीढ़ियाँ चढ़ने या दौड़ने पर सांस फूलती है, लेकिन, फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में हल्की गतिविधियाँ, जैसे बिस्तर ठीक करने, जूते के फीते बांधने या देर तक बात करने पर भी सांस फूल सकती है, सीधे लेटने पर सांस लेने में तकलीफ होना भी एक चेतावनी का संकेत हो सकता है और इसे नजरअंदाज करने के बजाय इकी जांच करवानी चाहिए, तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत कुछ लक्षणों के लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है, इनमें शामिल हैं, रात में अचानक सांस के लिए हाफते हुए जागना, पैरों या टखनों में सूजन, होंठों या उंगलियों के नाखूनों का नीला पड़ना, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, या सांस लेने के लिए रुके बिना कोई वाक्य पूरा न कर पाना,

टेस्ट करवाना बेहद जरूरी अगर सांस फूलने की समस्या लगातार बनी रहती है, बार-बार होती है या की जा रही गतिविधि के हिसाब

शेयर बाजार में निवेश के नाम पर यूपी के निवेशकों को करोड़ों की चपतय ने देहरादून से दबोचा आरोपी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार आरोपी का नाम विवेक कुमार है, जो मूल रूप से देहरादून का रहने वाला है, फिलहाल वह हरियाणा के गुरुग्राम में रह रहा था, जे के एडिशनल एसपी दीपक सिंह के मुताबिक इस गिरोह के लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लोगों से संपर्क करते थे, उन्हें शेयर बाजार की ट्रेनिंग देने के नाम पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता था, इसके बाद ग्रुप में शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश से मोटा मुनाफा होने के फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर लोगों को निवेश के लिए तैयार किया जाता था, लोगों को 14 घंटे डाउनलोड कराकर उसमें अकाउंट खुलवाया जाता था, शुरुआत में ऐप के डेमोवर्ड पर फर्जी मुनाफा दिखाया जाता था, जिससे निवेशकों को भरोसा हो जाता था, इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में पैसा जमा कराया जाता था, एसटीएफ के अनुसार, इस तरह निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कराए गए, उन्होंने बताया कि एसटीएफ की जांच में सामने आया कि ठगी से मिले पैसे को फर्जी कंपनियों के नाम से खोले गए बैंक खातों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके प्लेट से गिरफ्तार किया, उसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड, दो राउटर और 15,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं, इस मामले में ट्रान्सफर किया जाता था, इसके



बाद कई लेयर बनाकर रकम को यूएसडीटी में बदला जाता था और दुबई में बैठे गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाया जाता था, एसटीएफ ने विवेक कुमार सिंह को 19 सितंबर की रात करीब 8:20 बजे देहरादून के राजपुर थाने उसके प्लेट से गिरफ्तार किया, उसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड, दो राउटर और 15,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं, इस मामले में इससे पहले भी कई आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है, एसटीएफ के मुताबिक, विवेक कुमार सिंह के खिलाफ साइबर क्राइम थाने लखनऊ समेत अलग-अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं, उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने देश के अलग-अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस गिरोह से जुड़ी अब तक 3,087 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होने की बात एसटीएफ ने बताई है, गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड

पर लखनऊ लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके प्लेट से गिरफ्तार किया, उसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड, दो राउटर और 15,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं, इस मामले में इससे पहले भी कई आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है, एसटीएफ के मुताबिक, विवेक कुमार सिंह के खिलाफ साइबर क्राइम थाने लखनऊ समेत अलग-अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं, उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने देश के अलग-अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस गिरोह से जुड़ी अब तक 3,087 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होने की बात एसटीएफ ने बताई है, गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड

मिर्जापुर में रिश्तखोर पुलिसकर्मियों पर गाज, नो एंट्री में 500 रुपये लेकर ट्रक पास कराने पर 3 सिपाही निलंबित



मिर्जापुर: मिर्जापुर जिले में ट्रकों से अवैध वसूली के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कार्रवाई की है, नो एंट्री में गाड़ियों को पास कराने के नाम पर 500-500 रुपये वसूलने वाले तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है, गाड़ियों से अवैध एंट्री लेने के आरोप में ट्रैफिक सिपाही तेजु यादव, बरकछा चौकी के सिपाही मो. अंसार और आरुतोष गौतम पर यह गाज गिरी है, पुलिस अधिकारियों की इस सख्त कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है, जांच में पोल खुलते ही सर्वेड हुए तीन सिपाही, (टचकमव बमकपज: म्प्ट ठीतज) ट्रक मालिक ने बताया था रिश्तखोरी का वीडियो: यह पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के बरकछा रामटेक चौराहा स्थित पुलिस बूथ का है, हाईवे के प्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाले ट्रकों से सिपाही नो एंट्री में गाड़ियों को आस-पास की जांच में सही पाया गया आरोप: एसपी अपर्णा रजत कौशिक तक वीडियो पहुंचते ही उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया, उन्होंने तुरंत सदर सीओ जटारंकर मिश्र को पूरे मामले की निष्पत्ति जांच सीपी, जांच रिपोर्ट में ट्रकों से वसूली का आरोप पूरी तरह सही पाया गया, जिसके तुरंत बाद तीनों दोषी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया, शिकायतकर्ता का कहना था कि ट्रकों के खलासी पुलिस बूथ के अंदर जाकर रुपये रखते थे और तब गाड़ियाँ आगे बढ़ती थीं, गलत काम करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर तीन सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस कार्रवाई से जिले में अवैध वसूली करने वालों में खीसखट कार्रवाई: एसपी अपर्णा रजत फ का माहौल है, पास कराने के बदले पैसे वसूलते थे, इस करतूत से परेशान होकर एक ट्रक मालिक भोला सिंह ने छिपकर पूरा वीडियो बना लिया, भोला सिंह ने वसूली के दो-तीन वीडियो बनाकर 23 सितंबर को सीधे पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप पर भेज दिए, सीओ सदर की जांच में सही पाया गया आरोप: एसपी अपर्णा रजत

सही पाया गया, जिसके तुरंत बाद तीनों दोषी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया, शिकायतकर्ता का कहना था कि ट्रकों के खलासी पुलिस बूथ के अंदर जाकर रुपये रखते थे और तब गाड़ियाँ आगे बढ़ती थीं, गलत काम करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर तीन सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस कार्रवाई से जिले में अवैध वसूली करने वालों में खीसखट कार्रवाई: एसपी अपर्णा रजत फ का माहौल है, पास कराने के बदले पैसे वसूलते थे, इस करतूत से परेशान होकर एक ट्रक मालिक भोला सिंह ने छिपकर पूरा वीडियो बना लिया, भोला सिंह ने वसूली के दो-तीन वीडियो बनाकर 23 सितंबर को सीधे पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप पर भेज दिए, सीओ सदर की जांच में सही पाया गया आरोप: एसपी अपर्णा रजत

कौशिक तक वीडियो पहुंचते ही उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया, उन्होंने तुरंत सदर सीओ जटारंकर मिश्र को पूरे मामले की निष्पत्ति जांच सीपी, जांच रिपोर्ट में ट्रकों से वसूली का आरोप पूरी तरह सही पाया गया, जिसके तुरंत बाद तीनों दोषी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया, शिकायतकर्ता का कहना था कि ट्रकों के खलासी पुलिस बूथ के अंदर जाकर रुपये रखते थे और तब गाड़ियाँ आगे बढ़ती थीं, गलत काम करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर तीन सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस कार्रवाई से जिले में अवैध वसूली करने वालों में खीसखट कार्रवाई: एसपी अपर्णा रजत

इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 139वां स्थापना दिवसय महान विभूतियों की प्रदर्शनी के साथ 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' पर हुआ मंथन

प्रयागराज: पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले ऐतिहासिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बुधवार को 139वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, डेढ़ सदी के करीब पहुंचे इस संस्थान की पहचान केवल इसके भव्य भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस वैचारिक ऊर्जा में है जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर नीति-निर्माण, साहित्य, न्यायपालिका और प्रशासनिक ढांचे को गढ़ा है, प्रदर्शनी सजी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान दौर की चुनौतियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छम्ह) के आधुनिक आयामों पर भी विमर्श किया गया, विश्वविद्यालय परिसर में लगाई गई एलुमनाई की गैलरी इस बात का साक्षात् प्रमाण है कि ये संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने का केंद्र नहीं, बल्कि प्रतिभाओं की शाला रहा है, बात करें प्रदर्शनी की तो यूनिवर्सिटी में राजनेताओं में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गो. विंद बल्लभ पंत, साहित्य में महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, फिरोज गोरखपुरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अमरकांत, कमलेश्वर और विद्यानिवास मिश्र, न्यायविद और प्रशासक में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण, विनीत सारन, पंकज मित्तल, परित्त नौकरशाह बी.के. चतुर्वेदी, जिलोकीनाथ जैन और निखिल कुमार और कला और संस्कृति के क्षेत्र में गिम्मांशु घुलिया, साईद जाफरी, विनय पाठक और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुधीर धर केंद्र बनें, विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक दौर को याद करते हुए परित्त साहित्यकार यश मालवीय ने बताया कि उस समय के छात्रावास किसी गुरुकुल से कम नहीं थे, उन्होंने कहा, "इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृति का सृजन उगता था और छात्रावासों के कमरा, तब उसकी किरणें पहुंचती थीं, तारा, चंद जैसे छात्रावासों में कन्हैयालाल



139वां स्थापना दिवस

नंदन, बच्चन, कमलेश्वर जैसे दिग्गज रहे, कभी निराला जी आ जाते थे, कभी फिरोज साहब बैठ जाते थे, वह दौर केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के साहित्यिक-सांस्कृतिक परिवेश को प्राणवायु देता था, भूगोल विभाग के शोधार्थी अभिनव का मानना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिर्फ एक सेल्फी पॉइंट नहीं, पिछले कुछ वर्षों में योग्य शिक्षकों की नियुक्तियों के बाद शोध और पठन-पाठन का स्तर काफी संवरा है, आज देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र यहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं, संस्थान 139 वर्षों के अपने सफर को आगे भी उतनी ही मजबूती से जारी रखे हुए है, वहीं, विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर ने संस्थान की वर्तमान प्राथमिकताओं और भविष्य के रोडमैप को साझा किया, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय 140वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और ये विरासत केवल संज्ञा, न के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प है, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 200 से अधिक इलेक्टिव और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का पुराना दबदबा फिर से लौटने लगा है और इस दिशा में विशेष अकादमिक माहौल तैयार किया जा रहा है, पूरब का ये ऐतिहासिक संस्थान अपनी शानदार बौद्धिक धरोहर को आधार बनाकर नए युग के तकनीकी और अकादमिक बदलावों के साथ करने को तत्पर दिखाई दे रहा है,

इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज शुरू किए गए हैं, ताकि छात्रों का समग्र व्यक्तित्व विकास हो और वे वैश्विक जरूरतों के अनुरूप तैयार हों, कटिंग-एज विषयों पर शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं सिविल सेवा (CSE) में वहीं, विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर ने संस्थान की वर्तमान प्राथमिकताओं और भविष्य के रोडमैप को साझा किया, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय 140वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और ये विरासत केवल संज्ञा, न के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प है, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 200 से अधिक इलेक्टिव और

A woman with long brown hair, wearing a white tank top and light-colored striped pants, is sitting on a bed with a green sheet. She is leaning forward, holding her lower back with both hands, indicating pain or discomfort. The background shows a bedroom setting with a lamp and a plant.

A 3D rendering of two red, root-like structures on a blue surface. The structures are bulbous at the top and have many thin, branching roots extending downwards. They are positioned close to each other, with a bright orange glow between them, suggesting a chemical reaction or interaction. The background is a textured blue surface.

जी. राविर भंडारी कहते हैं कि ऑनलाइन अडैप्टिव रेडियोथेरेपी (वाल्) इन तकनीकों में एक अहम नई खोज है, जिसने कैंसर के सीधे इलाज के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। पारंपरिक रेडियोथेरेपी में, मरीज के शरीर का बू स्कैन एक बार (शुरुआत में) किया जाता है, और कई दिनों या हफ्तों तक पर आधारित इलाज के बीच संतुलन बनाने में ही है। एडवांस्ड रेडिएशन तकनीक, प्रिंसिपल मेडिसिन और एक मजबूत प्रिवेंटिव हेल्थकेयर प्रोग्राम के बीच तालमेल बिठाकर, हम कैंसर मरीजों के बचने की दर (सर्वाइवल रेट) को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए चौथी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है।



भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। शनिवार को भारतीय टीम ने फाइनल में ईरान को 37-34 से मात दी। इसके साथ भारत 2022 के बाद 2026 में अपने गोल्ड मेडल को बरकरार रखने में सफल रही। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने मैदान का चक्कर लगाते हुए वंदे मातरम गीत गाया। खास बात ये है कि ये ये एशियन गेम्स में भारत का चौथा महिला कबड्डी गोल्ड मेडल है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने जकार्ता में 2018 में हुए खेलों के अलावा हर एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। जकार्ता में उसे फाइनल में ईरान ने

हराया था। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराया (छत्ता) कप्तान ने कर दी बड़ी मांग इस शानदार जीत के बाद भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने कबड्डी को कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक खेलों में शामिल करने की मांग की। उन्होंने पछे से छक्का, ईरान एक बहुत अच्छी टीम है। उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ कहे मुक। जबले खेले हैं, चीनी ताइपे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सभी देशों में सुधार हो रहा है। और हम चाहते हैं कि कबड्डी सभी देशों में खूब आगे बढ़े ताकि भविष्य में इसे कॉमनवेल्थ

गेम्स और ओलंपिक में शामिल किया जा सके। जीत के बारे में बात करते हुए पुष्पा ने कहा कि टीम का पूरा ध्यान गोल्ड मेडल जीतने पर था। उन्होंने कहा, 'शुरु से ही हमारे दिमाग में यही बात थी (गोल्ड जीतना)। हमने सभी मैच एक ही सोच के साथ खेले। हम हर मैच जीतना चाहते थे, भले ही विरोधी टीम मजबूत हो। हर खिलाड़ी को पता था कि मैच को अपने पक्ष में कैसे करना है। तीसरा गोल्डमीजुदा एशियाई खेलों में भारतीय दल के लिए ये तीसरा गोल्ड है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। उसके बाद शूटिंग में सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम मुक। जबले में भारत गोल्ड मेडल दिलाया था। पुरुष कबड्डी टीम से भी उम्मीद भारतीय पुरुष कबड्डी टीम भी फाइनल में है, जिससे भारत को एक और गोल्ड मेडल की उम्मीद है। फाइनल में भारत का सामना ईरान से ही होगा। पुरुष कबड्डी टीम ने भी एक बार छोड़कर हमेशा स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष टीम भी जकार्ता में 2018 में फाइनल में ईरान से हारी थी लेकिन हांगकॉउ में 2022 में खिताब जीता था। मेडल टैली एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली में भारत अभी 27 मेडल के साथ 12वें स्थान पर है। जिसमें 3 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जबकि चीन 166 मेडल (103 गोल्ड, 38 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज) के

आम जनता को बड़ा झटका! अक्टूबर और दिसंबर में फिर बढ़ सकती है आपके लोन की म्डर रिपोर्ट



देश में होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की मासिक किस्त (म्डर) चुकाने वाले करोड़ों लोगों के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की शोध इकाई यानी एसबीआई रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर में होने वाली संभावित बढ़ोतरी और चौरफा बढ़ते दबाव को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (रुपे) आगामी अक्टूबर और दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में ब्याज दरों में 25-25 बेसिस पॉइंट (कुल 0.50) का इजाफा कर सकता है। ब्याज बढ़ेगी ब्याज दरें और क्या है वजह? एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस नीतिगत बदलाव के

पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण काम कर रहे हैं। खुदरा महंगाई दर का 6.5: के पार जाना: देश में खुदरा महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 4.82 फीसदी पर पहुंच गई है, जो जुलाई में 4.45 फीसदी थी। ग्रामीण इलाकों में यह दर और भी अधिक 5.23 फीसदी रही है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि आने वाले महीनों में यह महंगाई दर 6.5 फीसदी के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाएगी। यह सितंबर में 5.88 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 6.70 फीसदी तक पहुंच सकती है, जिसके बाद वर्ष 2027 की शुरुआत में ही यह 8 फीसदी से नीचे आ जाएगी। कच्चे तेल की कीमतें और आयातित महंगाई: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे

तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत जुलाई के 82.04 डॉलर से बढ़कर सितंबर में 109.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इसके चलते आयातित महंगाई पहले ही 7.75 फीसदी की ऊंची दर पर चल रही है, जो घरेलू बाजार में चीजों की कीमतें बढ़ा रही है। महंगाई का सामान्यीकरण और बढ़ता दबाव रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर जताई गई है कि महंगाई अब केवल चुनिंदा वस्तुओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सामान्यीकरण (लमदमतसंपर्जपवद) शुरू हो चुका है। एसबीआई रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई सूचकांक में योगदान देने वाली वस्तुओं की संख्या जो

एशियन गेम्स 2026: तालिबान की डर से छोड़ा देश, अफगान महिला साइक्लिस्ट ने सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास

तालिबान की डर से अपना देश छोड़ने वाली साइक्लिस्ट फरीबा हाशमी ने एशियन गेम्स 2026 में एक प्रेरणादायक कहानी लिखी है। उन्होंने बुधवार को महिलाओं की व्यक्तिगत रोड रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो 2002 के बाद एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ी बन गईं। न्यूज एजेंसी (एफ) के अनुसार, फरीबा ने कहा, 'मैं अभी अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा, 'मेरा जन्म ऐसे देश में हुआ था जहां सपने देखने वाली महिलाओं पर हमले होते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मुझे उम्मीद है कि अगली पीढ़ी यहां आएगी और बिना किसी डर के अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगी। फगान महिला साइक्लिस्ट फरीबा हाशमी अफगान महिला साइक्लिस्ट फरीबा हाशमी (एफ) फरीबा इटली क्यों चली गईं बता दें कि 23 वर्षीय फरीबा पांच साल पहले अपना देश छोड़कर इटली में बस गई हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वह अफगानिस्तान से भाग गई थीं। क्योंकि तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और खेल सहित अन्य क्षेत्रों पर रोक लगा दी है। इससे डल से अफगान



महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी फरीबा को उम्मीद है कि उनकी जीत से कई अन्य अफगान महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। हाशमी ने कहा, 'उन्होंने हमारी आजादी छीन ली, उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया। यह सिल्वर मेडल अफगान महिलाओं के साहस को दिखा सकता है, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरे पीछे कई देशों की लाखों महिलाओं का भी यही सपना है और वे मेरे साथ खड़ी हैं।' 15 साल की उम्र से साइक्लिजिंग शुरू फरीबा ने 15 साल की उम्र में अपनी बहन युलुज के नक्शेकदम पर चलते हुए साइक्लिजिंग शुरू की, जो खुद भी एक इंटरनेशनल साइक्लिस्ट हैं। दोनों बहनों में से किसी ने भी पहले कभी बाइक नहीं चलाई थी और 2017 में

अपनी पहली रेस में भाग लेने से पहले वे पड़ोसियों से साइकिल उधार लेकर घंटों तक चलाती थीं। फरीबा हाशमी अपनी बहन युलुज हाशमी के साथ (एफ) फरीबा ने न्यूज एजेंसी रीपटर्स को बताया, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान के फरयाब में महिलाएं साइकिल चलाएंगी। हमें लगा था कि यह छोटी बात होगी, लेकिन इससे काफी हलचल मच गई। मैं हमेशा ट्रेन तक जाने के लिए पुरुषों जैसे कपड़ों में पहनें, मैं कभी हार नहीं मानना। घृणाहर्ती और उम्मीद है कि हम लॉस एंजिल्स ओलंपिक में फिर से देख पाएंगे। फरीबा ने ये भी कहा कि मैं यहां बिना किसी मैकेनिक और बिना किसी तैयारी के आई थी। हम नेशनल फंडेशन से एक व्यक्ति को साथ लाए थे, और वह सिर्फ कार चला रहा था। हम खुद ही बाइक ठीक कर रहे थे। मैं खुद ही अपनी मैकेनिक थी। मैं खुद ही बाइक धो रही थी। अफगानिस्तान तीन मेडल जीत चुका है एशियन गेम्स में अफगानिस्तान ने अब तक 3 मेडल अपने नाम कर चुका है। जिसमें दो ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल है। फरीबा हाशमी ने महिला रोड रेस में सिल्वर जीता है।

(एफ) भारत का 28 साल का इंटरजार खल्ट हुआकर्म मल्लेश्वरी ने 1998 के एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था और अगले 28 सालों तक भारत को वेटलिफ्टिंग में पोटियम तक पहुंचने का इंटरजार करना पड़ा। चानू ने 28 सालों में एशियन गेम्स में भारत का पहला वेटलिफ्टिंग मेडल जीता। इस जीत ने मीराबाई चानू की उपलब्धियों की सूची में एक कमी को भी पूरा किया, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते थे, लेकिन इस इवेंट मेडल हमेशा उनकी



खेलों और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के अलावा एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता है। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में भारत के 28 साल का इंटरजार किया खल्ट मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में भारत के 28 साल का इंटरजार किया खल्ट

पंजाब: त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों को बंपर तोहफा, व। में सीधे 8: की भारी बढ़ोतरी



इ: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारों से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (व।) में 8 फीसदी की बढ़ोतरी करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस फैसले पर मुहर लगी, जिससे पिछले कई हफ्तों से चला आ रहा गतिरोध और राज्यव्यापी आंदोलन अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। दो किस्तों में मिलेगा लाभ, अक्टूबर से बढ़ेगी सैलरी बैंकेनेट से मिली जानकारी के मुताबिक, इस 8: की बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता अब 42: से बढ़कर 50: हो गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इस बड़े हुए भत्ते को 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाएगा, यह नई दरें सितंबर 2026 के वेतन से ही प्रभावी मान ली गई हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2026 को कर्मचारियों के खातों में जो सैलरी आएगी, वह भारी बढ़ोतरी के साथ क्रेडिट होगी। सरकारी खजाने पर ₹250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ इस बड़े वित्तीय फैसले से जहां राज्य के लाखों परिवारों को त्योहारों के सीजन में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी,

वहीं पंजाब के सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, हालांकि, सरकार का कहना है कि वे इस खर्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कर्मचारियों की गरिमा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाद से सुलझा विवाद: महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी यूनियनों के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद बातचीत की कमान संभाली, उन्होंने एकराव का रास्ता छोड़कर संवाद का जरिया चुना। इस बैठक में न सिर्फ डीए बढ़ाने पर सहमति बनी, बल्कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य रूप से बैठक करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही, सरकार ने महिला कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक और संवेदनशील फैसला लिया है। अब राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को बिना किसी तनाव के निभा सकें। 70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां शीब 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां किसी तनाव के निभा सकें, 70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां मुख्यमंत्री मान ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए निक व्यवस्था की रीढ़ है। एक संतुष्ट। नुहैया कराई है। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (वै) और अन्य लंबित भत्तों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

कर्मचारी ही सिस्टम को बेहतर बना सकता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक बिना किसी भ्रष्टाचार और पूरी पारदर्शिता के साथ ककराव का रास्ता छोड़कर संवाद का जरिया चुना। इस बैठक में न सिर्फ डीए बढ़ाने पर सहमति बनी, बल्कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य रूप से बैठक करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही, सरकार ने महिला कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक और संवेदनशील फैसला लिया है। अब राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को बिना किसी तनाव के निभा सकें। 70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां शीब 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां किसी तनाव के निभा सकें, 70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां मुख्यमंत्री मान ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए निक व्यवस्था की रीढ़ है। एक संतुष्ट। नुहैया कराई है। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (वै) और अन्य लंबित भत्तों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

वेटलिफ्टिंग में भारत का 28 साल का इंटरजार खल्ट, मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल

भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने बुधवार को एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली भारतीय एथलीट मीराबाई का ये एशियन गेम्स में पहला मेडल था। मीराबाई ने महिलाओं के 49 किग्रा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने वेटलिफ्टिंग में मेडल जीतने के लिए भारत के 28 साल के इंटरजार को खल्ट किया। मीराबाई ने ओलंपिक में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण सहित तीन पदक तथा राष्ट्रमंडल

‘खाकी’ से ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ तक, इस एक्टर ने अजय देवगन संग किया काम, जानिए क्या बोला इंस्पेक्टर ‘गायतोंडे’



हैदराबाद: जब भी दृश्यम की बात होती है, तो गायतोंडे और उसके आइकॉनिक वन-लाइनर्स को भला कैसे भुलाया जा सकता है। अब, जब दृश्यम: द कन्क्लूजन फ्रैंचाइजी का बहुप्रतीक्षित आखिरी अध्याय लेकर आ रही है, तब 2015 से विजय सलगांवकर और उसके परिवार पर बाज की नजर रखने वाला एक खलसा है, गायतोंडे। इस बार सलगांवकर परिवार का पीछा करते हुए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी को, शिश में वह एसी क्राइम थ्रिलर ऑफिर राजवीर सिंह तोमर जिसका किरदार जयदीप अहलावत निभा रहे हैं, के साथ हाथ मिलाता है, ताकि इस केस की पूरी गुथी सुलझाई जा सके। अजय देवगन के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए कमलेश सावंत ने दृश्यम के सेट से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया और फिल्म की पहली किस्त से जुड़ा एक यादगार पल बताया। अभिनेता ने कहा, '2004 में मैंने अजय देवगन के साथ खाकी की थी, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्शन बताया। अभिनेता ने कहा, '2004 में मैंने अजय देवगन के साथ खाकी की थी, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्शन बताया। अभिनेता ने कहा, '2004 में मैंने अजय देवगन के साथ खाकी की थी, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्शन बताया।

देवगन, तबू, श्रिया सरन, रजत कपूर, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, कमलेश सावंत, इशिता दत्ता, और मृणाल जाधव समेत कई बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे, जो इस चर्चित फ्रैंचाइजी के अंतिम अध्याय को एक दमदार कलाकारों की टोली के साथ पेश करेंगे स्टारस्टुडियो 18 की पेशकश और पनोरमा स्टुडियोज के बबड़ा है, क्या वह आखिरी बार भी कानून को मात देने में कामयाब होगा? अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित दृश्यम: द कन्क्लूजन अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है और सलगांवकर और उसके परिवार के सामने इस बार दांव पहले से कहीं बड़ा है, क्या वह आखिरी बार भी कानून को मात देने में कामयाब होगा? अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित दृश्यम: द कन्क्लूजन में अजय

‘नजरें मिलेंगी..लेकिन हटेंगी नहीं’, भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ से विक्की कौशल का फर्स्ट लुक आउट, फुल स्वैग में दिखे एक्टर



हैदराबाद: संजय लीला भंसाली 'हीरामंडी' के बाद अब फिल्म लव एंड वॉर से धमाका करने जा रहे हैं, फिल्म साल 2027 के पहले ही ग्रीने में रिलीज होने जा रही है। इससे पहले फिल्म की लीड स्टारकास्ट के एक के बाद एक फर्स्ट लुक सामने आ रहे हैं। बीते दिनों रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के फिल्म से फर्स्ट लुक सामने आए थे, जिन्होंने इंटरनेट पर धमाका मचाया हुआ है। आज 26 सितंबर को विक्की कौशल का भी फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। भंसाली प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट

लुक शेयर किया है। मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विक्की कौशल का फर्स्ट लुक शेयर किया है। विक्की कौशल अपने फर्स्ट लुक में दमदार लग रहे हैं। विक्की कौशल का लव एंड वॉर से फर्स्ट लुक शेयर कर भंसाली प्रोडक्शन ने लिखा है, नजरें मिलेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं। विक्की कौशल के फर्स्ट लुक की बात करें तो वह पूरी स्वैग में नजर आ रहे हैं। उन्होंने गुह में सिगरेट दबाई हुई और लाइटर से जलते दिख रहे हैं। विक्की की आंखें बता रही हैं कि उनका किरदार एक

अलग ही शैल में नजर आने वाला है। विक्की कौशल के फर्स्ट लुक पर सेलेब्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गये हैं। आलिया भट्ट ने विक्की कौशल के फर्स्ट लुक पर कई फायर इमोजी पोस्ट कर इसे फायर बताया है। विक्की के छोटे भाई सनी कौशल ने लिखा है, अरे भाई भाई.. भाई और फायर इमोजी शेयर किए हैं। सोनम कपूर ने भी विक्की कौशल के फर्स्ट लुक पर फायर इमोजी पोस्ट किए हैं। विक्की के फैन ने भी उनके इस लुक पर कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी की बाढ़ ला दी है। बता दें, इससे पहले आए रणवीर कपूर के फर्स्ट लुक ने भी संजय लीला भंसाली के फैंस को धौंका दिया था और सेलेब्स ने भी खूब तारीफ की थी, वहीं, आलिया भट्ट की कैबरे लुक में आई पहली झलक अभी तक सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फिल्म से एक-एक कर तीनों लीड स्टारकास्ट के फर्स्ट लुक सामने आ चुके हैं, जो दर्शकों को बेचीनी बढ़ाने के लिए काफी है। अब इन सभी लुक को देखने के बाद दर्शकों को फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार है। फिल्म 21 जनवरी 2027 को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है। अगर आप फिल्म लव एंड वॉर से रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक करें...

सलमान खान की 'मातृभूमि' को नहीं मिली ब्छ से राहत, चीन से जुड़े कनेक्शन के कारण अटकी फिल्म की रिलीज?



सलमान खान की बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस के सामने एक और रुकावट आती दिख रही है। खबर है कि चीन से इसके कनेक्शन के कारण फिल्म के सर्टिफिकेशन में देरी हो रही है। इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि सीबीएफसी द्वारा अगले हफ्ते फिल्म की स्क्रीनिंग किए जाने की उम्मीद के बाद फिल्म का काम आगे बढ़ सकता है। हालांकि, एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मामले में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस की स्क्रीनिंग अगले हफ्ते सेंसर बोर्ड के सामने होनी है, जिससे इसके जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने की अटकलें लगने लगीं। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी कोई स्क्रीनिंग तय नहीं की गई है और जिपे-पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से फिल्म की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिल्म की सीबीएफ स्क्रीनिंग अभी तक तय नहीं हुई है। सोर्स ने बताया, 'काश ये खबर सच होती। लेकिन भारी मन से मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि दुख की बात है कि इसकी सीबीएफसी स्क्रीनिंग के बारे में कोई अपडेट नहीं है। चीन से जुड़े मामले

की वजह से फिल्म अभी भी अटकी हुई है। 2026 में रिलीज होने की संभावना पर बात करते हुए सोर्स ने कहा, 'जैसा कि पहले कहा गया है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मामले का सुलझता है। अगर यह जल्दी हो जाता है, तो मेकर्स निश्चित रूप से 2026 में ही फिल्म को सिनेमाघरों में लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके लिए पर्याप्त खाली स्लॉट उपलब्ध नहीं हैं। वरना, इसे 2027 के लिए टाल दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स इस मामले को सुलझाने के लिए संबंधित सरकार, एरि अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि मामला सुलझने के बाद फिल्म सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेगी, जिसके बाद मेकर्स इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने की दिशा में काम कर सकेंगे, हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है। यह फिल्म भारत और चीन के बीच 2020 में हुई सैन्य झड़प पर आधारित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों में सुधार के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने फिल्म के कुछ खास कंटेंट को लेकर चिंता जताई है। इस साल की शुरुआत में आई रिपोर्ट्स से संकेत मिला था कि आधिकारिक मंजूरी पाने के लिए फिल्म से 'चीन' के जिक्र को पूरी तरह हटाया जा सकता है।

रिलीज से एक दिन पहले 'द पैराडाइज' ने छापे करोड़ों, इतना होगा नानी की फिल्म का डे 3 कलेक्शन, जानें रनटाइम और बहुत कुछ

नानी और राघव जुयाल स्टारर 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म का क्रेज साफ दिख रहा है और इसकी शानदार एडवांस बुकिंग के आंकड़े इसका सबूत हैं। 'द पैराडाइज' ने पूरे भारत में प्री-सेल्स में 40 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और यह नानी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने की राह पर है। यह सब तब हो रहा है जब मेकर्स ने फिल्म का थिएट्रिकल ट्रेलर जारी नहीं किया, क्योंकि वे फिल्म से जुड़े सस्पेंस को बनाए रखना चाहते थे। लगता है कि उनका यह फैसला उनके हक में काम कर रहा है। सीकनेल्स के अनुसार, 'द पैराडाइज' ने 6 शो की तारीखों के लिए एडवांस बुकिंग में 41.33 करोड़ रुपये की कमाई की है, ब्लॉक सीटों को छोड़कर यह आंकड़ा 34.29 करोड़ है। पहले दिन (गुरुवार, 24 सितंबर) 20.25 करोड़ की कमाई के साथ सबसे आगे है। हैदराबाद सबसे ज्यादा योगदान देने वाला शहर बनकर उभरा है, जहां अकेले इसी शहर से फिल्म ने 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस गॉस कमाई की है। फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुख्य कारण तेलुगु भाषी बाजार है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सबसे अच्छा रिएप्स मिला है, जबकि कर्नाटक का भी इसमें अहम योगदान है। 'द पैराडाइज' के लिए चुनौती यह होगी कि फिल्म रिलीज होने के बाद हिंदी बेल्ट और अन्य भाषाओं में इसका आंकड़ा और बढ़ जाए। हालांकि टिकट विंडो पर दबदबा बनाने के लिए फिल्म को एक बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जैसे-जैसे रिलीज का समय नजदीक आ रहा है, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और एडवांस बुकिंग जोरों पर है। आंकड़ों के अनुसार, 'द पैराडाइज' नानी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग देने की राह पर है। उनके करियर की पिछली सबसे बड़ी ओपनिंग 'हिट: द थर्ड केस' के नाम थी, जिसने पहले दिन



दुनिया भर में लगभग 43 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब उम्मीद है कि 'द पैराडाइज' उस आंकड़े को पार कर जाएगी। मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, इसकी वर्ल्डवाइड ओपनिंग 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। 'द पैराडाइज' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से 'ए' सर्टिफिकेट मिला है। एडल्ट रेटिंग के बावजूद, फिल्म की एडवांस बिक्री जबरदस्त रही है। नानी के इस जबरदस्त फिल्म का रनटाइम लगभग 165 मिनट है। नानी की पीरियड एक्शन ड्रामा की थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है, खासकर उन बाजारों में जहां इसकी सबसे ज्यादा पकड़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नानी ने वह हासिल कर लिया है जो बड़े-बड़े स्टार्स के लिए भी एक सपने जैसा होता है। हैदराबाद में, 78 में से 77 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में यह

फिल्म दिखाई जाएगी। यह इस साल की सबसे बड़ी रिलीज और नानी के लिए एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। 'द पैराडाइज' के बारे में 'द पैराडाइज' फिल्म 'दसरा' के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला की दूसरी फिल्म है। यह फिल्म दुनिया भर में 24 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी, जबकि इसके पेड प्रीमियर शो 23 सितंबर से शुरू होंगे। इसकी कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद पर आधारित है और यह नानी के किरदार 'जदल' के इर्द-गिर्द घूमती है। जदल एक पिछड़े आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है जो न्याय के लिए एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनता है। कायद लोहार भी मुख्य कलाकारों में शामिल हैं, जबकि सोनाली कुलकर्णी नानी की मां 'सम्माका' की अहम भूमिका निभा रही हैं। राघव जुयाल, जो इस फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं, विलेन का किरदार निभा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रालय ने 18वें प्वाँथ में 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग पर लगाई रोक



केंद्रीय मंत्रालय ने 18वें प्वाँथ में 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग पर लगाई रोक। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केरल राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा आयोजित 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरलम (प्लैथ्थ) में दिखाई जाने वाली 31 फिल्मों को दिखाने की मंजूरी नहीं दी। मंजूरी उन फिल्मों के लिए नहीं दी गई जिन्हें आधिकारिक तौर पर फेस्टिवल के लिए चुना गया था। यह फेस्टिवल 25 से 30 सितंबर तक तिरुवनंतपुरम में होने वाला है, मंजूरी न पाने वाली फिल्मों में एक मलयालम फिल्म भी शामिल है। बता दें, फिल्म फेस्टिवल में बिना सेंसर वाली फिल्में दिखाने की छूट

मंत्रालय को सौंपी, साथ ही उन फिल्मों की थीम का छोटा सारांश भी दिया। इसके बाद, मंत्रालय के कहने पर अकादमी ने 40 फिल्मों की डिटेल्ड सिनॉप्सिस और स्क्रीनर भेजे, जिसके बाद ही 31 फिल्मों को दिखाए जाने की इजाजत नहीं दी गई।

पर्यटन, संस्कृति और सिनेमा मंत्री पी. सी. विष्णुनाथ ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मांग की कि वह चलचित्र अकादमी की सितेशन कमिटी द्वारा चुनी गई कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग की अनुमति न देने के अपने फैसले पर फिर से